

खास-खबरें

एक जनवरी 2027 से व्हाट्सऐप इस्तेमाल करने का तरीका बदलेगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: एक जनवरी 2027 से व्हाट्सऐप के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव हो सकता है। सरकार सिम बाईंडिंग से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रही है। इस व्यवस्था के तहत संदेश भेजने वाले अनुप्रयोगों को संबंधित मोबाइल नंबर और उसके सिम कार्ड के बीच संबंध सुनिश्चित करना होगा। ऐसे में जिन उपयोगकर्ताओं के फोन में संबंधित सिम कार्ड मौजूद नहीं होगा, उन्हें सेवा इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। सिम बाईंडिंग का उद्देश्य मोबाइल नंबर के वास्तविक उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित करना और डिजिटल संचार की सुरक्षा मजबूत करना है। इस व्यवस्था में संबंधित मोबाइल नंबर के सिम कार्ड को उपकरण से जोड़कर उसकी पुष्टि की जाती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि संदेश भेजने वाली सेवा उसी नंबर से जुड़ी रहे, जिसका सिम उपयोगकर्ता के पास उपलब्ध है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने चलाए स्वच्छता अभियान

नईदुनिया ब्यूरो, नोएडा: वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने विशेष अभियान 6.0 के तहत स्वच्छता, कार्यस्थल के बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कीं। दो से 23 अक्टूबर 2026 तक चले इन कार्यक्रमों में निगम के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों ने भाग लिया। अभियान के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की गई। कार्यालय परिसर से कचरा, अनुपयोगी सामग्री और पुरानी वस्तुएं हटाई गईं। नालियों तथा पानी की टैंकियों की सफाई और रखरखाव भी किया गया। दो अक्टूबर को नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया। पांच अक्टूबर को क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई।

छह अक्टूबर को कार्यालय परिसर की नालियों से गंदगी और कचरा हटाया गया तथा पानी की टैंकियों की सफाई की गई। सात अक्टूबर को लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी पुरानी और टूटी वस्तुओं को परिसर से हटाया गया। आठ अक्टूबर को स्वच्छता के महत्व पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। नौ अक्टूबर को प्रबंध निदेशक ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण किया। 12 अक्टूबर को कर्मचारियों ने ‘कचरा किसका, जिम्मेदारी किसकी’ विषय पर सार्वजनिक स्थान पर नुकड़ नाटक प्रस्तुत किया। 13 अक्टूबर को महाप्रबंधक ने कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। 14 अक्टूबर को कार्यालय की दीवार पर स्वच्छता संबंधी चित्रकारी की गई। इसके बाद 15 अक्टूबर को नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित हुई। 16 अक्टूबर को नई दिल्ली के पोचनपुर स्थित राजकीय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता कार्यशाला आयोजित की गई। 19 अक्टूबर को कार्यालय परिसर में स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण बनाए।

टाटा संस में नेतृत्व को लेकर विवाद एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल पर नोएल टाटा ने उठाए सवाल

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन की पांच वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया है। टाटा इस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा ने इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कंपनी के सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को पत्र लिखकर 17 सितंबर को हुई निदेशक मंडल की बैठक से संबंधित अभिलेख मांगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नोएल टाटा ने 26 अक्टूबर को लिखे पत्र में बैठक की ध्वनि और दृश्य रिकॉर्डिंग, हस्ताक्षरित कार्यवृत्त, मतदान संबंधी अभिलेख और कंपनी पंजीयक के पास जमा किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने तीन सितंबर को हुई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक के अभिलेख भी मांगे हैं। सितंबर में निदेशक मंडल की बैठक में चंद्रशेखरन को 21 फरवरी 2027 से अगले पांच वर्षों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नोएल टाटा ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आपत्ति लगाया है कि बैठक के मूल और संशोधित कार्यसूची में पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। उन्होंने चयन समिति के गठन और आवश्यक मतदान प्रक्रिया का पालन किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। इसके अलावा, उन्होंने निदेशक मंडल के सदस्य और टाटा इस्ट्स के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन के संभावित हितों के टकराव का मुद्दा उठाया है।

स्पेशल खबर

उपकरणों के निपटान की पहल, 75 अनुपयोगी सूचना एवं दूरसंचार उपकरण चिह्नित...

केंद्रीय रेशम बोर्ड में स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन पर जोर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड विशेष अभियान 6 के माध्यम से स्वच्छता, अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव और कार्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दे रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ वातावरण तैयार करना, लंबित मामलों को कम करना, अनुपयोगी सामग्री का निपटान करना और कार्यक्षमता बढ़ाना है।

अभियान के तहत बोर्ड के कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, कार्यस्थलों, गलियारों, भंडारण कक्षों और सार्वजनिक सुविधाओं की सफाई एवं रखरखाव किया जा रहा है। कार्यालयों के शौचालयों के नवीनीकरण के साथ परिसर, रास्तों, पार्किंग स्थलों और पेयजल केंद्रों की सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अनावश्यक वनस्पतियों



और खरपतवार को हटाने की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं।

अभिलेख प्रबंधन के अंतर्गत पुराने दस्तावेजों और फाइलों की समीक्षा की जा रही है। अभिलेख कक्षों तथा भंडारण स्थलों को व्यवस्थित किया जा रहा है।

नईदुनिया

एक नवंबर से बदलेंगे पाँच नियम, रसोई गैस से लेकर कर और यातायात तक पड़ेगा असर

नए महीने की शुरुआत में आम लोगों के खर्च और रोजमर्रा की सुविधाओं से जुड़े नियमों में संभावित बदलाव, घरों और कारोबार पर रहेगा प्रभाव



संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कुछ मामलों में कर वापसी की स्वचाहित मंजूरी की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा, पांच करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले ऐसे कारोबारियों के लिए नई विवरणी व्यवस्था की जानकारी दी गई है, जो सीधे

ग्राहकों को वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तमिलनाडु में शराब के भुगतान का नया नियम: एक नवंबर से तमिलनाडु में एक हजार रुपये से अधिक कीमत वाली शराब की बोलत खरीदने पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया जा रहा है। राज्य विपणन निगम के इस

निर्णय के तहत ऐसी खरीद के लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुंबई-पुणे मार्ग पर मालवाहक वाहनों पर रोक: मुंबई-पुणे द्रुतगति मार्ग के नए संपर्क मार्ग पर एक नवंबर से मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। इस रोक में छोटे

व्यावसायिक वाहन, सामान ढोने वाली गाड़ियां और टाटा एस जैसे वाहन भी शामिल होंगे। निजी कारों और यात्री बसों को आवागमन की अनुमति रहेगी।

मोबाइल पर दिखाई देगा फोन करने वाले का नाम: दूरसंचार विभाग के निर्देश के अनुसार, एक नवंबर से चौथी और पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क पर आने वाले कॉल के साथ फोन करने वाले का पंजीकृत नाम दिखाने की व्यवस्था लागू की जानी है। इससे अज्ञान नंबरों से आने वाली कॉल की पहचान करने में सहायता मिलेगी। इन बदलावों में कुछ का प्रभाव पूरे देश में होगा, जबकि शराब के भुगतान और राजमार्ग संबंधी नियम विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हैं।

भारत-नीदरलैंड व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नीदरलैंड की यात्रा के दौरान 26 अक्टूबर को वहां की सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, सांसदों और प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें कीं। इनका उद्देश्य भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना था।

पीयूष गोयल ने नीदरलैंड के विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्री स्जोर्ड स्जोर्ड्समा, आर्थिक मामलों एवं जलवायु मंत्री होलीन हर्बर्ट तथा नॉर्थ हॉलैंड प्रांत के किंग्स कमिश्नर आर्थर वान डाइक से मुलाकात की। उन्होंने नीदरलैंड की संसद के विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग समिति और सीनेट की यूरोपीय मामलों संबंधी समिति के सदस्यों के साथ भी चर्चा की। बैठकों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों और भारत-यूरोपीय संघ की व्यापक आर्थिक साझेदारी पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

यात्रा का प्रमुख कार्यक्रम भारत-नीदरलैंड व्यापार मंच रहा। इसकी सह-अध्यक्षता पीयूष गोयल और स्जोर्ड स्जोर्ड्समा ने की। इसमें भारतीय और डच उद्योग जगत के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसरों, बाजार तक पहुंच बढ़ाने, निवेश साझेदारियों को मजबूत करने और आपूर्ति



- पीयूष गोयल ने की उच्चस्तरीय बैठकें
- दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा
- लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भारत-नीदरलैंड व्यापार मंच में लिया हिस्सा

श्रृंखलाओं के एकीकरण पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने नीदरलैंड की प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें भी कीं। इनमें अर्धचालक प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन एवं माल ढुलाई, ऊर्जा, औद्योगिक समाधान, प्रौद्योगिकी और खुदरा कारोबार से जुड़ी कंपनियां शामिल थीं। इन बैठकों में कारोबारी प्राथमिकताओं और दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

माइक्रोसॉफ्ट का 60 हजार कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों की संख्या और परिचालन खर्च को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्वेच्छक सेवा समाप्ति योजना पेश की है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बदले उनके पद और वेतनमान के अनुसार एकमुश्त राशि देने का प्रस्ताव है। यह राशि अधिकतम एक वर्ष के वेतन के बराबर हो सकती है।

कंपनी को इस योजना के दायरे में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। बताया गया है कि लगभग 60 हजार कर्मचारियों तक यह योजना पहुंच सकती है। हालांकि, इनमें से किनसे कर्मचारियों को वास्तव में प्रस्ताव

► भारत समेत चार देशों के पात्र कर्मचारियों के लिए स्वेच्छक सेवा समाप्ति योजना

► एआई और तकनीकी ढांचे पर बढ़ते खर्च के बीच कदम

दिया जाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। पात्र कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी और उन्हें एक दिसंबर तक अपना निर्णय लेना होगा।

माइक्रोसॉफ्ट में कुल लगभग 2.23 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें करीब 23 हजार भारत में हैं। यह योजना कंपनी में निर्धारित स्तर 70 या उससे नीचे के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। वरिष्ठ स्तर के पदों पर कार्यरत कर्मचारी इसके दायरे में

नहीं बताए गए हैं। कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी प्रणालियों के विकास पर बड़े पैमाने पर खर्च कर रही है। ऐसे में यह योजना खर्च घटाने और संगठनात्मक प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है।

माइक्रोसॉफ्ट की मुख्य कार्मिक अधिकारी एमी कोलमैन ने कहा कि स्वेच्छक सेवा समाप्ति का प्रस्ताव कंपनी के लिए नया प्रयोग है और इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों को अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देने, नए कौशल सीखने और कंपनी के भीतर उपलब्ध दूसरे अवसर वलाशने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही।

बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच दो औद्योगिक विवादों का सौहार्द्रपूर्ण समाधान

बिहार ग्रामीण बैंक के 10,900 से कर्मचारियों को मिलेगा 77.69 करोड़ रुपये का लाभ

नईदुनिया ब्यूरो, पटना: बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबे समय से लंबित दो औद्योगिक विवादों का 22 और 23 अक्टूबर को सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत सहायक श्रम आयुक्त, पटना के प्रयासों से हुए इन समझौतों से बैंक के 10,900 से अधिक कर्मचारियों को कुल लगभग 77.69 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है। इसमें लगभग 9.02 करोड़ रुपये का आवर्ती वार्षिक लाभ भी शामिल है।

पहला समझौता 22 अक्टूबर को बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ, पटना और बैंक प्रबंधन के बीच हुआ। इससे 8,400 कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। इस समझौते के तहत करीब 67.17 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ निर्धारित किया गया है। इसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांगों, जैसे प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, कार्य भत्तों में सुधार, वेतन और बैंक प्रबंधन के बढोतरी, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया। दूसरा

मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

► संसेक्स 8 अंक फिसला

► ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दबाव, वाहन, मीडिया और औषधि कंपनियों के शेयरों में खरीदारी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का संसेक्स आठ अंक गिरकर 73,599 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी तीन अंक फिसलकर 22,750 पर आ गया। कारोबार के दौरान निजी बैंकों, ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में अधिक बिकवाली देखी गई। दूसरी ओर, वाहन, मीडिया और औषधि कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा।

बाजार में सीमित गिरावट के बीच निवेशकों की नजर विभिन्न क्षेत्रों के शेयरों के प्रदर्शन पर रही। पिछले कारोबारी सत्र सोमवार को बाजार में तेजी दर्ज की गई थी। इस बीच, जल शोधन क्षेत्र में काम

करने वाली कंपनी एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज का आरंभिक सार्वजनिक निर्यात मंगलवार से खुल गया। कंपनी ने प्रति शेयर मूल्य दायरा 313 से 330 रुपये तक निवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

एशियाई बाजारों में मंगलवार को मिला-जुला कारोबार रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3.09 प्रतिशत बढ़कर 5,638 पर पहुंच गया। जापान का निककेई सूचकांक 1.73 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63,268 पर बंद हुआ। वहीं, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.73 प्रतिशत गिरकर 23,041 पर आ गया। अमेरिकी बाजारों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई थी। डाउ जोन्स 0.28 प्रतिशत, नैसडेक 0.82 प्रतिशत और एसएंडपी 500 सूचकांक 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले सात दिनों में भारतीय बाजार से 3,011 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की।



निधि योजना के तहत 4,194 उद्यमों के लिए 775.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 532 ऋणों के लिए 1,662.71 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई है। प्रति ऋणकर्ता गारंटी की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है।

कारोबार से जुड़े नियमों को सरल बनाने के लिए केंद्र और राज्यों में कुल 47,957 अनुपालन आवश्यकताओं में कमी की गई है। इनमें 22,290 का डिजिटलीकरण, 16,141 का सरलीकरण, 5,255 को अपराध की श्रेणी से बाहर

करना और 4,271 आवश्यकताओं को समाप्त करना शामिल है। जन विश्वास अधिनियमों के माध्यम से केंद्रीय कानूनों के 900 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

श्रम व्यवस्था में सुधार के तहत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। छंटेनी या प्रतिष्ठान बंद करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता संबंधी सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी गई है। कारखानों और संविदा श्रमिकों से संबंधित कुछ प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 17 क्षेत्रों में स्वतः स्वीकृति मार्ग का विस्तार किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान भारत में कुल 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। वित्त वर्ष 2025-26 में यह निवेश 94.53 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से अब तक 8.5 लाख से अधिक मंजूरियां प्रदान की गई हैं। इस मंच पर केंद्र और राज्य सरकारों की कुल 3,779 सेवाएं उपलब्ध हैं।

बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच दो औद्योगिक विवादों का सौहार्द्रपूर्ण समाधान

बिहार ग्रामीण बैंक के 10,900 से कर्मचारियों को मिलेगा 77.69 करोड़ रुपये का लाभ



तहत करीब 67.17 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ निर्धारित किया गया है। इसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांगों, जैसे प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, कार्य भत्तों में सुधार, वेतन और बैंक प्रबंधन के बढोतरी, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया। दूसरा

समझौता 23 अक्टूबर को बिहार ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन और बैंक प्रबंधन के बीच हुआ। इससे लगभग 2,500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस समझौते के तहत करीब 10.52 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 9.02 करोड़ रुपये का आवर्ती वार्षिक लाभ शामिल है।

मारुति सुजुकी का मुनाफा 26 प्रतिशत घटा दूसरी तिमाही में 2,466 करोड़ रहा लाभ

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफा पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 26.4 प्रतिशत घटकर 2,466 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी की परिचालन से आय 26 प्रतिशत बढ़कर 53,355.5 करोड़ रुपये पहुंच गई।

कंपनी के अनुसार, परिष्कृत एशिया में जारी युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में बढोतरी हुई। इसके अलावा, निवेशित अतिरिक्त धनराशि के बाजार मूल्य में बदलाव से हुए नुकसान ने भी मुनाफे पर असर डाला। दूसरी तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ 17.1 प्रतिशत घटकर

2,803.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 3,382 करोड़ रुपये था। हालांकि, पिछली तिमाही की तुलना में परिचालन लाभ में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी ने वाहन बिक्री का नया तिमाही रिकॉर्ड बनाया। जुलाई से सितंबर के दौरान कुल 6,96,654 वाहन बेचे गए, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 26.5 प्रतिशत अधिक हैं। घरेलू यात्री वाहन बाजार में छोटी कारों की बिक्री 35.9 प्रतिशत और खेल उपयोगिता वाहनों की बिक्री 68.2 प्रतिशत बढ़ी। इसके साथ कंपनी की घरेलू यात्री वाहन बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 40.8 प्रतिशत हो गई।